

भारत का विदेश व्यापार :2012-13 (अप्रैल-दिसंबर)*

इस लेख में, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इन्टेलिजेन्स एंड स्टेटिस्टिक्स (डीजीसीआइ एण्ड एस) द्वारा रिलीज़ किए गए डाटा के आधार पर अप्रैल-दिसंबर 2012-13 के दौरान भारत के 'पण्य-व्यापार - कार्यनिष्पादन' की समीक्षा की गई। इसमें, इस अवधि के दौरान भिन्न-भिन्न जिनसवार तथा दिशावार विवरणों का भी विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख बातें

2012-13 के दौरान (दिसंबर 2012 तक) भारत का व्यापारिक कार्यनिष्पादन कमजोर बना रहा और व्यापारिक घाटा बढ़कर 147.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जिससे परिलक्षित हुआ कि आयातों की तुलना में निर्यात कार्यनिष्पादन में गिरावट, 2012-13 की पहली छमाही में, और अधिक जिनस समूहों तथा साथ ही निर्यात गंतव्यों में परिलक्षित हुई क्योंकि इस अवधि के दौरान, वैश्विक मंदी से संबंधित चिंताएं और भी गहरी हो गई थीं। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात, जो कुल पण्य निर्यातों में लगभग 64 प्रतिशत का योगदान करते हैं, उनमें आए संकुचन ने भारत के निर्यात कार्यनिष्पादन पर काफी असर डाला जिसमें से श्रम सधन क्षेत्रों, जैसे हस्तशिल्प वस्त्र तथा रत्न एवं आभूषण में काफी अधिक गिरावट आई। व्यापार क्षेत्र की बहाली, अधिकांशतः, वैश्विक मांग के फिर से आने पर ही टिकी है। आइएमएफ के नवीनतम प्रोजेक्शन के अनुसार वैश्विक व्यापार मात्रा, 2012-13 की 2.8 प्रतिशत के मुकाबले 2013 में 3.8 प्रतिशत तक बढ़ने की अपेक्षा है। अप्रैल-दिसंबर 2012-2013 की अवधि के दौरान भारत के व्यापार कार्यनिष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- अप्रैल-दिसंबर 2012 के दौरान निर्यात के आंकड़े 214.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के थे जिनसे 5.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान 29.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- इस अवधि में आयातों का स्तर 361.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का था, जिससे 0.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की

गई जबकि अप्रैल-दिसंबर 2011 में 35.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

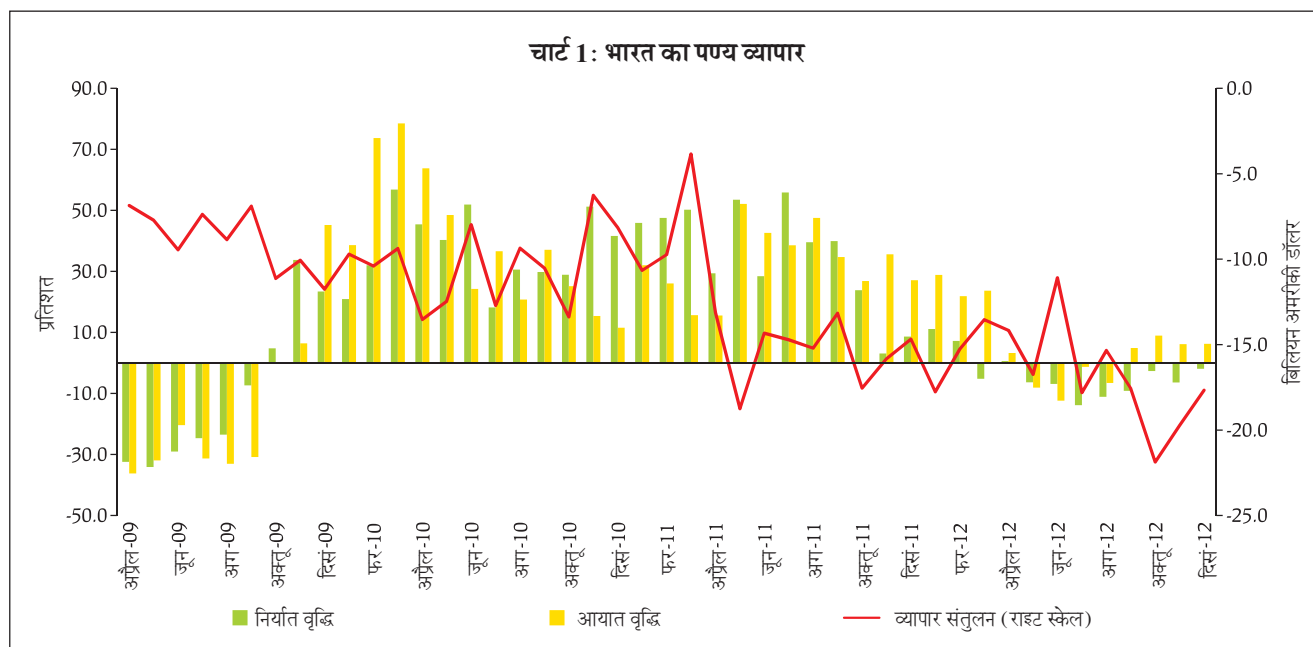
- आयातों में यह गिरावट मुख्यतः सोने तथा गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयातों में हुई। कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी के बावजूद पेट्रोलियम, तेल तथा लुब्रिकेन्ट्स (पीओएल) के आयात में वृद्धि जारी रही।
- आयात के मुकाबले निर्यात में गिरावट अधिक होने से अप्रैल-दिसंबर 2012 में 147.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ जिसमें से पीओएल सेक्टर का घाटा 85.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा और इसी का घाटे में सबसे बड़ा हिस्सा था।
- 2012-13 की पहली छमाही के दौरान जिनसों के पण्य निर्यातों से संबंधित भिन्न-भिन्न (डिस्प्रीग्रेटिड) आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्यातों में यह गिरावट मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातों के मामले में वृद्धि की गतिशीलता उलट जाने के कारण हुई है।
- खासकर जर्मनी, इटली, यू.के. तथा बेल्जियम में धीमी मांग की वजह से यूरॉपियन यूनियन के देशों को किए जाने वाले निर्यातों पर काफी बुरा असर पड़ा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से अन्य अर्थव्यवस्थाओं में हुए प्रतिकूल स्पिलओवर्स को परिलक्षित करते हुए अधिकांश उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को भारत के निर्यात, 2011-12 की तदनुसूची अवधि की तुलना में 2012-13 में या तो गिरे या उनमें गिरावट की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत का पण्य व्यापार

निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2012

हालांकि इस अवधि में 'निर्यात कार्य निष्पादन' कमजोर बना रहा मगर 2012-13 की पहली छमाही की तुलना में 2012-13 की तीसरी तिमाही में निर्यातों में गिरावट अपेक्षाकृत कम रही जो कि सरकार द्वारा जून 2012 में निर्यात प्रोत्साहन के जो उपाय किए गए थे उनकी वजह से परिलक्षित हुई (चार्ट-1)। उन्नत तथा उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में फैली वैश्विक अनिश्चितताओं और कमजोरियों के कारण भारत की बाह्य मांग पर बुरा असर पड़ना जारी रहा। अप्रैल-दिसंबर 2012 के दौरान निर्यात 214.1

* आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। लेख का पिछला इश्यू रिजर्व बैंक बुलेटिन के दिसंबर 2012 के अंक में प्रकाशित किया गया था।



बिलियन अमरीकी डॉलर थे जिससे 5.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई क्योंकि अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान निर्यात 226.6

बिलियन अमरीकी डॉलर हुए थे और 29.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (तालिका - I)।

तालिका 1 : भारत का पण्य व्यापार

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

मदें	अप्रैल-दिसंबर	
	2011-12 आर	2012-13पी
1	2	3
निर्यात	226.6 (29.6)	214.4 (-5.5)
जिसमें से : तेल	42.3 (49.5)	40.0 (-5.4)
गैर तेल	184.3 (25.8)	174.4 (-5.5)
स्वर्ण	5.0 (31.6)	4.7 (-6.0)
गैर-तेल, गैर-स्वर्ण	179.3 (25.6)	169.7 (-5.5)
आयात	363.9 (35.2)	361.3 (-0.7)
जिसमें से : तेल	111.0 (47.6)	125.4 (13.0)
गैर तेल	252.9 (30.4)	235.9 (-6.7)
स्वर्ण	41.7 (46.3)	37.8 (-9.4)
गैर-तेल, गैर-स्वर्ण	211.2 (27.6)	198.1 (-6.2)
व्यापार घाटा	-137.3	-147.2
जिसमें से : तेल	-68.7	-85.4
गैर तेल	-68.6	-61.8
गैर तेल, गैर स्वर्ण	-31.9	-28.7

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े वृद्धि दर के प्रतिनिधिक हैं

स्रोत: डीजीसीआइ एण्ड एस

जिंसवार तथा गंतव्यवार निर्यात - अप्रैल-सितंबर 2012-13

भिन्न-भिन्न किस्म के जिन्सवार निर्यात आंकड़े दर्शाते हैं कि वृद्धि में कमी अथवा गिरावट, जो पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू हुई उसने 2012-13 की पहली छमाही में और गति पकड़ ली (तालिका 2)। वे प्रमुख मदें जो पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में सकारात्मक वृद्धि क्षेत्र से निकल कर चालू वर्ष में नकारात्मक वृद्धि क्षेत्र में आ गई उनमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद तथा वस्त्र और लौह खनिज शामिल हैं। लौह खनिज के निर्यातों की वृद्धि में गिरावट इनके कारण परिलक्षित हुई - कमजोर खनन गतिविधि का निरंतर प्रभाव, 2011 के दिसंबर अंत से निर्यात ड्यूटी में वृद्धि, लौह खनिज निर्यातों के मालभाड़े में वृद्धि, राज्यस्वामित्व वाले खनिजकर्ताओं द्वारा लौह खनिज की कीमत में लगभग 8-13 प्रतिशत की बढ़ोतरी। हालांकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रूप से धीमी वृद्धि रही है मगर कुछ छोटे उप सेक्टरों अथवा जिंसों ने बढ़ी हुई वृद्धि भी दर्ज की है। इनमें प्रमुख हैं तम्बाकू, गेहूँ, चावल, अभिसंस्करणीकृत खनिज धातु, तथा गलीचों का निर्माण, जो कुल निर्यातों के 8 प्रतिशत से भी कम बनते हैं।

गंतव्यवार आंकड़े दर्शाते हैं कि यूरोपियन यूनियन तथा एशियाई देशों में निर्यात को बड़ा आघात लगा है। यहां ईयू को निर्यात, जो कि भारत के पण्य निर्यातों का 16.3 प्रतिशत

तालिका 2 : प्रमुख जिनसों का भारत से निर्यात

(प्रतिशत)

जिनस समूह/ अवधि	प्रतिशत हिस्सा			संबंधित भारत परिवर्तन		
	2011-12	2011-12:छ1	2012-13:छ1	2011-12: छ1	2011-12: छ2	2012-13: छ1
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिक उत्पाद	15.0	12.1	16.2	4.8	5.1	3.1
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	12.2	9.6	14.1	5.4	4.8	3.6
कच्ची धातुएं और खनिज	2.8	2.5	2.1	-0.6	0.3	-0.5
विनिर्मित वस्तुएं	60.6	61.6	62.9	23.1	1.4	-2.7
जिनमें से:						
चमड़ा और मैन्युफैक्चर्स	1.5	1.6	1.7	0.6	0.2	-0.1
रसायन और संबंधित उत्पाद	12.1	11.7	13.3	4.7	2.1	0.8
इंजीनियरिंग वस्तुएं	22.2	23.0	22.3	8.3	0.4	-2.1
वस्त्र और वस्त्रोत्पाद	9.2	9.3	9.1	3.3	0.1	-0.8
रत्न आभूषण	14.7	15.0	15.3	5.8	-1.4	-0.6
पेट्रोलियम उत्पाद	18.3	19.0	18.7	10.6	2.0	-1.5
अन्य	6.1	7.3	2.2	2.1	-1.2	-5.3
जोड़	100.0	100.0	100.0	40.5	7.3	-6.4

स्रोत : डीजीसीआइ तथा एस पर आधारित

है 11.2 प्रतिशत गिर गया और (जापान को छोड़कर) एशियाई देशों का हिस्सा भी अप्रैल-सितंबर के दौरान 8.4 प्रतिशत सिकुड़ गया जबकि यह हिस्सा 28.1 प्रतिशत होता है (तालिका III)। यद्यपि विभिन्न उपायों (बॉक्स I) की वजह से भारत का निर्यात धीरे-धीरे और अधिक विविधीकृत हुआ है तथापि अधिकांश एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में आई वृद्धि की गिरावट का असर 2012-13 की पहली छमाही में भारत के निर्यातों पर भी पड़ा। खास तौर पर निर्यातों-मुखी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं अर्थात् चीन, जापान, सिंगापुर, हाँगकाँग, दक्षिण कोरिया तथा मलेशिया से बाह्य मांग में काफी गिरावट देखी गई। इन अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण गतिविधि कम हो जाने से भारत से इन्पुट्स की मांग पर असर पड़ा है। 2011-12 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अफ्रीकी तथा लेटिन अमरीकी देशों को किए जाने वाले निर्यातों में वृद्धि भी अप्रैल-सितंबर 2012 के दौरान बहुत कम रही।

जैसा कि तालिका IV और V में दिखाया गया है, 2011-12 की पहली छमाही के दौरान निर्यातों में दर्ज की गई उच्च वृद्धि सुविधिीकृत थी। जैसे ही उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में साक्ष्यित हुई वृद्धि संबंधी चिंताएं, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी फैली, तो इसका असर 2011-12 की दूसरी छमाही से भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए कुल निर्यात से विकासशील एशिया का सापेक्ष भारत योगदान 2011-12 की दूसरी छमाही में घटकर 4.3 प्रतिशतता बिंदुओं पर आ गया और 2012-13 की पहली

छमाही के दौरान 2.4 प्रतिशतता बिंदुओं पर नकारात्मक पर आ गया (2011-12 की पहली छमाही में 13.1 प्रतिशतता बिंदु)। इसी प्रकार भारत की निर्यात वृद्धि में अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका में नए खोजे गए बाजारों का सापेक्ष योगदान भी 2012-13 की पहली छमाही में तेजी से गिरा। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के निर्यातों पर न केवल अमरीका तथा

तालिका 3 : प्रमुख क्षेत्रों में भारत का निर्यात

(प्रतिशत हिस्सा)

क्षेत्र/देश	2010-11	2011-12	2011-12	2012-13
	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-सितंबर	
1	2	3	4	5
I. ओईसीडी देश	33.2	33.8	33.2	35.3
ईयू	18.3	17.2	17.1	16.3
उत्तरी अमरीका	10.6	12.0	11.8	14.4
यूएस	10.1	11.4	11.2	13.7
एशिया तथा ओशियानिया	2.8	3.0	2.6	2.9
अन्य ओईसीडी देश	1.5	1.6	1.8	1.8
II. ओपीईसी	21.3	19.0	18.3	21.8
III. पूर्वी यूरोप	1.1	1.1	1.0	1.3
IV. विकासशील देश	38.2	40.8	39.3	40.8
एशिया	27.9	29.7	28.7	28.1
सार्क	4.6	4.4	3.9	4.7
अन्य एशियाई विकासशील देश	23.3	25.3	24.7	23.3
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना	6.2	6.0	5.2	4.4
अफ्रीका	6.3	6.7	6.2	7.7
लैटिन अमरीका	4.0	4.4	4.4	5.1
V. अन्य / अविनिर्धारित	6.2	5.3	8.2	0.8
कुल निर्यात	100	100	100	100

स्रोत : डीजीसीआइ एण्ड एस आंकड़ों से संकलित

बॉक्स 1: भारत के निर्यातों के विविधीकरण के लिए किए गए नीतिगत उपाय: गंतव्यवार

हाल के वर्षों में भारत ने निर्यातों के देशवार विविधीकरण के संदर्भ में एक सुस्पष्ट बदलाव (शिफ्ट) किया है। वस्तुतः वैश्विक वृद्धि की परिवर्तनशील गतिशीलता को पहचानते हुए भारत की व्यापारिक नीति ने बाजार विविधीकरण कार्यनीति अपनाने की जरूरत को माना। कार्यनीतिगत योजना के एक भाग के रूप में सरकार ने भारत के निर्यातों के बाजार विविधीकरण तथा भारत की एक ब्रांड छवि बनाने की प्राथमिकता को काफी महत्त्व दिया। बाजार विविधीकरण के प्रति भारत की कार्यनीति में इन बातों पर बल दिया गया है: (i) पारंपरिक उन्नत देशों के बाजारों में अपनी उपस्थिति बनाए रखना (ii) पारंपरिक निर्यात बाजारों में उत्पाद प्रदान करने में वैल्यू चेन में ऊपर उठना तथा (iii) नए खुले उभरते बाजारों में विपणन और उत्पाद दोनों की संभावनाएं खोजना।

भारत के गंतव्यवार निर्यातों की अंतर्कालिक तुलना दर्शाती है कि भारत के कुल पण्य निर्यातों में ईएमडीई का हिस्सा 1990 के दशक के मध्य से शनैः शनैः बढ़ा है। 1991 में बनी गई आर्थिक नीति के साथ ही शुरू हुई 'लुकईस्ट नीति' ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापारिक लिंकेज को बढ़ावा दिया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से सरकार ने निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपायों का मिश्रण कर एक अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान किया। इन उपायों में राजकोषीय प्रोत्साहन, सांस्थानिक बदलाव, कार्यविधि का तार्किकीकरण, और समूचे विश्व में बाजार पहुंच बनाने के लिए बढ़े हुए प्रयास शामिल थे।

2006 में सरकार ने एक फोकस बाजार योजना (एफएमएस) शुरू की जिसने संभाव्य बाजार में भारत के बाजार हिस्से को बढ़ाने की कार्यनीतिगत आवश्यकता को रेखांकित किया। एफएमएस के अंतर्गत सरकार ने अधिसूचित देशों में सभी उत्पादों के निर्यातों की एफओबी वैल्यू के साथ ड्यूटी क्रेडिट सुविधा को जोड़ने की अनुमति दी। एफएमएस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने वाले निर्यातकों को उच्च माल भाड़ा लागत तथा जो अन्य कठिनाइयां आती हैं उन्हें दूर करना था। शुरूआत से ही एफएमएस के अंतर्गत अधिसूचित देशों की सूची को धीरे-धीरे विस्तारित किया गया। 2008-09 से 2011-12 के बीच 29 नए देशों को एफएमएस की परिधि में लाया गया है। अन्य योजनाओं जैसे बाजार लिंकड फोकस उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) के स्कोप को भी बढ़ाया गया है। एफएमएस, विशेष एफएमएस तथा बाजार लिंकड फोकस उत्पाद योजना के कवरेज को 2012-13 में और अधिक व्यापक बनाया गया है (जून 2012 तथा दिसंबर 2012)।

ईएमडीई में निर्यात बाजार खोजने पर बढ़ते नीतिगत ध्यान से उच्च वृद्धि गंतव्यों जैसे चीन, सिंगापुर तथा हाँगकाँग जैसी एशिया पूर्व तथा दक्षिणपूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने भारत के निर्यात परिदृश्य को आच्छादित किया है और हाल के वर्षों में यह तीसरी, चौथी और पांचवीं पोजीशन पर रहा है। न केवल संयुक्त अरब अमीरात ही भारतीय निर्यातों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है बल्कि इन वर्षों में अन्य ईएमडीई ब्राजील, इंडोनेशिया तथा सऊदी अरब में भी निर्यातों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

तालिका 4 : प्रमुख व्यापार भागीदार अर्थव्यवस्थाओं का वृद्धिगत कार्यनिष्पादन

अवधि	(प्रतिशत)							
	ति1-2011	ति2-2011	ति3-2011	ति4-2011	ति1-2012	ति2-2012	ति3-2012	ति4-2012
देश								
जापान	0.2	-1.7	-0.5	-0.1	3.3	3.9	0.4	0.1
यूरो क्षेत्र (17 देश)	2.4	1.6	1.3	0.6	-0.1	-0.5	-0.6	-0.9
संयुक्त राज्य अमरीका	1.8	1.9	1.6	2.0	2.4	2.1	2.6	1.5
चीन	9.4	9.6	9.7	9.1	8.1	7.6	7.4	7.9
हाँगकाँग	7.8	5.1	4.3	2.8	0.7	1.2	1.3	..
सिंगापुर	9.7	1.6	6.0	3.6	1.5	2.3	0.0	1.5
कोरिया	4.0	3.5	3.7	3.4	2.9	2.3	1.5	1.6
इंडोनेशिया	6.6	6.5	6.6	6.4	6.4	6.3	6.2	6.1
मलेशिया	5.0	4.3	5.7	5.2	5.1	5.6	5.2	..
ब्राजील	4.1	3.3	2.3	1.4	0.7	0.4	1.0	..
दक्षिण अफ्रीका	4.0	3.7	3.2	3.0	2.4	2.8	2.6	..

.. : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : वृद्धि दरें सौजन्य के हिसाब से समायोजित की जाती हैं (हाँगकाँग, सिंगापुर तथा मलेशिया को छोड़कर)

स्रोत : ओईसीडी : सिंगस्टैट डाटा बेस, मंथली स्टैटिस्टिकल बुलेटिन बैंक नेगारा मलेशिया।

यूरोपियन यूनियन जैसे पारंपरिक बाजारों की कमजोर आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का असर पड़ा बल्कि एशिया, अफ्रीका, तथा लेटिन अमरीका, जैसे अपेक्षाकृत नए बाजारों की मंदी का भी असर पड़ा जो कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आए प्रतिकूल स्पिल ओवर्स से प्रभावित हुए प्रतीत हुए।

तालिका 5 : भारत की निर्यात वृद्धि में क्षेत्रवार सापेक्ष भारत परिवर्तन

	(प्रतिशत)				
	2010-11: छ1	2010-11: छ2	2011-12: छ1	2011-12: छ2	2012-13: छ1
यूरोपियन यूनियन	4.3	6.7	6.2	-0.2	-1.9
उत्तरी अमरीकी	3.6	3.1	5.2	3.1	1.7
अन्य ओईसीडी	1.9	1.5	1.5	1.2	0.0
ओपीईसी (ओपेक)	5.4	11.8	5.0	-0.8	2.2
पूर्वी यूरोप	0.6	0.6	0.3	0.1	0.2
विकासशील एशिया	8.3	10.2	13.1	4.3	-2.4
अफ्रीका	2.9	3.2	2.1	1.6	1.0
लैटिन अमरीका	3.4	0.9	1.7	1.0	0.3
अन्य	5.2	6.6	5.4	-2.7	-7.6
निर्यात वृद्धि	35.6	44.5	40.5	7.3	-6.4

आयात (अप्रैल-दिसंबर 2012)

अप्रैल-दिसंबर 2012-13 के दौरान, पण्य आयात 361.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के थे जबकि 2012-13 की इसी अवधि में ये 363.9 बिलियन अमरीकी डॉलर थे जिससे 0.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज हुई (अप्रैल-दिसंबर 2011-12 में 35.2 प्रतिशत)। आयातों की वृद्धि दर में गिरावट, सोने तथा गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयातों में हुई गिरावट के कारण आई। जहां पहले में यह गिरावट 2012-13 के प्रारंभिक महीनों के दौरान कस्टमड्यूटी में बढ़ोतरी के असर को परिलक्षित करती है वहीं बाद वाले में यह, निर्यात संबंधी मद्दों और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में समग्र मंदी से कम आयात मांग को ही अधिकांशतः परिलक्षित करती है। एक वर्ष पूर्व के 111.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2012-13 में इस अवधि के दौरान तेल आयात 125.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहे। कच्चे तेल की कीमतों की प्रवृत्ति तालिका 6 में प्रदर्शित की गई है।

जिसवार तथा गंतव्यवार आयात (अप्रैल-सितंबर 2012-13)

जिसवार आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि 2012-13 की पहली छमाही में पेट्रोलियम तेल तथा लुब्रिकेंट्स (पीओएल) का आयात, जो कि कुल पण्य आयातों का लगभग 34 प्रतिशत बनता है वह 2012-13 की पहली छमाही में 5.8 प्रतिशत पर बढ़ा (तालिका 7 तथा चार्ट 2)। अप्रैल-सितंबर 2012 के दौरान कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों (भारतीय

तालिका 6 : कच्चे तेल की कीमतों में प्रवृत्तियां

(अमरीकी डॉलर/बैरल)

अवधि	दुबई	ब्रेन्ट	डब्लूटीआइ*	भारतीय बास्केट**
1	2	3	4	5
2005-06	53.4	58.0	59.9	55.7
2006-07	60.9	64.4	64.7	62.5
2007-08	77.3	82.3	82.3	79.2
2008-09	82.1	84.7	85.8	83.6
2009-10	69.6	69.8	70.6	69.8
2010-11	84.2	86.7	83.2	85.1
2011-12	109.4	113.9	96.8	111.9
2012-13 (ति1)	106.2	108.9	93.4	106.9
2012-13 (ति2)	106.2	110.0	92.2	107.4
2012-13 (ति3)	107.2	110.5	88.1	108.3

* वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट

** कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की संरचना है 'सोर ग्रेड्स' के लिए ओमान और दुबई का औसत तथा स्वीड ग्रेड के लिए ब्रेन्ट (डेटिड) 1 अप्रैल 2011 से 65.2 : 34.8 के अनुपात में।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी : वर्ल्ड जेम डाटा एण्ड कमेडिटी : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार।

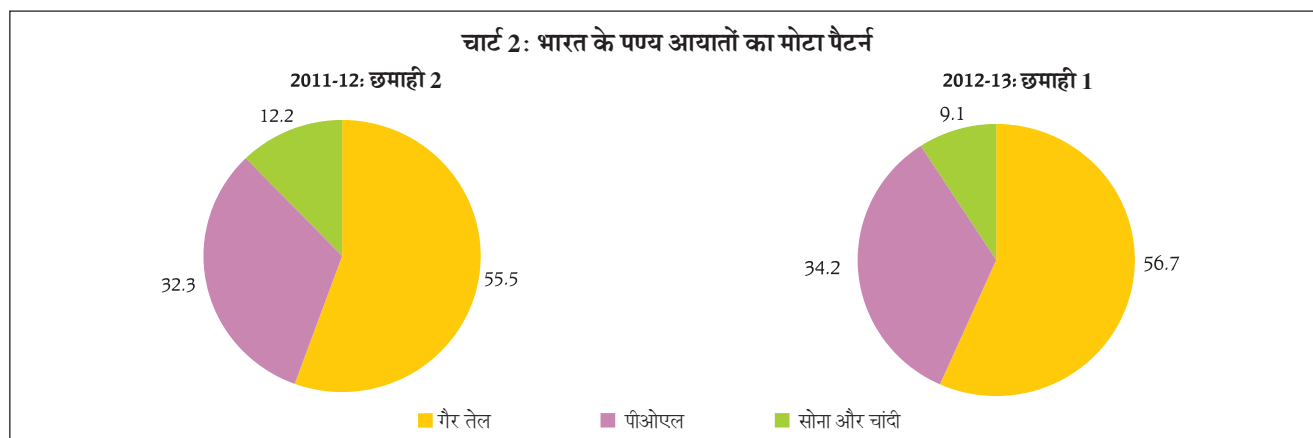
बास्केट) में 3.6 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद पीओएल आयातों में सकारात्मक वृद्धि अनिवार्यतः मात्रात्मक अर्थों में वृद्धि को परिलक्षित करती है। पूंजीगत माल तथा निर्यात संबंधी वस्तुओं हेतु आयात मांग में संकुचन, मुख्यतः, कम निवेश गतिविधि और धीमी निर्यात मांग के कारण हुआ। पूंजीगत वस्तुओं में 'मशीनटूल्ज', मशीनरी (इलैक्ट्रिकल तथा गैर इलैक्ट्रिकल दोनों), वाहन (ट्रांसपोर्ट) उपकरण, और 'इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं ने, कम वृद्धि दर्ज की। 2011-12 की पहली छमाही में 74.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2012-13 की पहली छमाही में सोने और चांदी के आयात

तालिका 7 : प्रधान जिंसों का आयात

(प्रतिशत)

जिंस/समूह	2011-12	2011-12: छ1	2012-13: छ1	2011-12: छ1	2011-12: छ2	2012-13: छ1
	प्रतिशत शेयर्स			आयात वृद्धि में भारत अंशदान		
1	2	3	4	5	6	7
1. पेट्रोलियम कच्चा तेल तथा उत्पाद	31.7	31.1	34.2	14.6	12.0	1.8
2. पूंजीगत वस्तुएं	20.3	19.8	19	6.2	4.9	-1.5
3. सोना और चांदी	12.5	13	9.1	7.6	2.9	-4.2
4. ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक रसायन	3.9	3.9	4.1	1.1	0.9	0.1
5. कोयला, कोक तथा ब्रिकेट्स इत्यादि	3.6	3.9	3.5	2.0	2.2	-0.5
6. उर्वरक	2.4	1.9	2.1	0.1	2.2	0.2
7. मेटैलिफेरस ओर्स, धातु स्क्रेप इत्यादि	2.7	2.8	3	1.3	0.7	0.1
8. लौह तथा स्टील	2.5	2.3	2.4	0.1	0.7	0.0
9. पल्स, प्रेशियस तथा अर्द्ध प्रेशियस स्टोन्ज़	5.7	6.5	4.2	0.5	-3.6	-2.5
10. अन्य	14.7	14.8	18.4	4.5	4.2	2.9
कुल आयात	100	100	100	38.1	27.1	-4.0

स्रोत : डीजीसीआइ एण्ड एस आंकड़ों के आधार पर।



में 32.6 प्रतिशत की गिरावट आई जिसका कारण अंशतः जनवरी तथा मार्च 2012 में सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी¹। निर्यात संबंधी मदों में से बहुमूल्य मोती, अर्ध बहुमूल्य स्टोन्स तथा टेक्सटाइल यार्न का आयात वैश्विक मांग गिरने की वजह से प्रभावित हुआ।

देशवार आयातों से संबंधित आंकड़ों से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि 2012-13 की पहली छमाही से चीन भारत के लिए आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है और कुल पण्य आयातों में उसका हिस्सा 11.9 प्रतिशत है जिसके बाद यू.एस. का हिस्सा 8.4 प्रतिशत तथा सऊदी अरब का हिस्सा 6.8 प्रतिशत है। भारतीय आयातों में इन सभी देशों का हिस्सा 2012-13 की पहली छमाही में बढ़ा है। 2012-13 की पहली छमाही में यू.एस.ए. तथा स्विट्जरलैंड से आयातों में गिरावट के बावजूद ये देश भारतीय आयातों के महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं और कुल पण्य आयातों में इनका हिस्सा क्रमशः 5.2 प्रतिशत तथा 4.6 प्रतिशत बना हुआ है। यूरोपियन यूनियन से आयात में गिरावट के कारण भारत के कुल पण्य आयातों में इसके हिस्से में गिरावट आई और यह 2011-12 की पहली छमाही के 12.1 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 की पहली छमाही में 11.1 प्रतिशत पर आ गया (तालिका 8)।

व्यापार घाटा

आयातों की तुलना में पण्य निर्यातों में तेजी से संकुचन के कारण व्यापार घाटा अप्रैल-दिसंबर 2011-12 के 137.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2012-13 में 147.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। निवल तेल

आयात, भारत के व्यापार घाटे में एक प्रमुख अड़चन रहा जिसमें काफी बड़ा घरेलू ऊर्जा घाटा शामिल था। अप्रैल-दिसंबर 2012 में निवल तेल आयात कुल व्यापार घाटे के 60.5 प्रतिशत थे जबकि अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान मात्र 50 प्रतिशत थे।

II. विश्व व्यापार

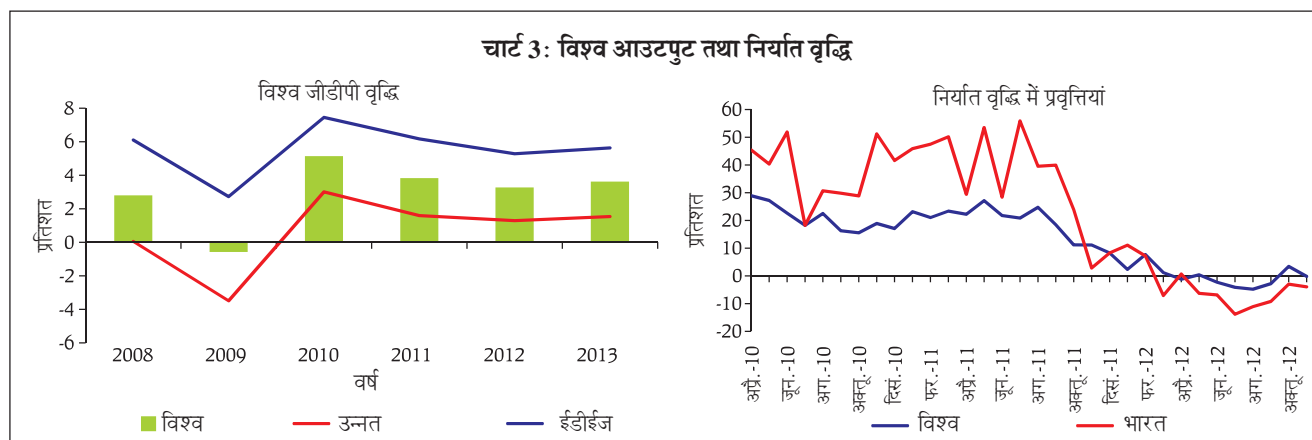
तालिका 8 : भारत के आयात में समूहों / देशों का हिस्सा

(प्रतिशत हिस्सा)

क्षेत्र/देश	2010-11	2011-12	2011-12	2012-13
	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-दिसंबर	
1	2	3	4	5
I. ओईसीडी देश	30.6	30.2	30.1	26.9
ईयू	12.0	11.9	12.1	11.1
फ्रांस	1.0	1.9	0.8	0.9
जर्मनी	3.2	3.3	3.3	3.1
यूके	1.5	1.6	1.6	1.4
उत्तरी अमरीका	6.0	5.6	5.6	5.7
यूएस	5.4	5.0	5.1	5.2
एशिया तथा ओशियानिया	5.4	5.7	5.7	5.2
अन्य ओईसीडी देश	7.2	7	6.7	4.9
II. ओपेक (ओपीईसी)	33.6	35.5	34.9	39
III. पूर्वी यूरोप	1.5	1.7	1.4	1.9
IV. विकासशील देश	33.0	32.3	33.2	31.9
एशिया	27.1	25.6	26.6	25.3
सार्क	0.6	0.5	0.6	0.6
अन्य एशियन विकासशील देश	26.5	25.3	26.1	24.7
जिनमें से:				
पीपुल्ज रिपब्लिक ऑफ चाइना	11.8	11.8	11.8	11.9
अफ्रीका	3.6	4	4.2	3.8
लैटिन अमरीका	2.4	2.4	2.4	2.9
V. अन्य / अविनिर्दिष्ट	1.3	0.3	0.4	0.3
जोड़	100	100	100	100

स्रोत : डीजीसीआइ एण्ड एस से संकलित।

¹ जनवरी 2013 में सोने के आयात पर कस्टम ड्यूटी 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गई थी।



2012 में विश्व व्यापार की मात्रा की वृद्धि में काफी हद तक कमी आई क्योंकि उन्नत तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं दोनों पर व्यापार इंटर लिंकेज के कारण असर पड़ा। कुल विश्व निर्यात के मुकाबले भारत के निर्यात कार्यानिष्पादन में गिरावट ज्यादा मुखर रही। आगे की ओर देखें तो यूरो क्षेत्र तथा अमरीका में वृद्धि के समक्ष कुछ कम हुए जोखिमों की पृष्ठभूमि में 2013 में वैश्विक वृद्धि में थोड़ी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तदनुसार, विश्व व्यापार संभावनाएं धीरे-धीरे सुधरेगी और आईएमएफ ने भी 2012 के 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2013 में 3.8 प्रतिशत विश्व व्यापार मात्रा में उच्चतर वृद्धि प्रोजेक्ट की है (चाई 3)।

दूसरी तिमाही तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर क्रॉस कंट्री तुलना दर्शाती है कि अधिकांश उन्नत

अर्थव्यवस्थाओं तथा ईएमडीई ने या तो गिरावट दिखाई है या निर्यातों में धीमी वृद्धि प्रदर्शित की है। तथापि (इंडोनेशिया को छोड़कर) इन अर्थव्यवस्थाओं में से भारत के मामले में गिरावट काफी अधिक थी। विश्व निर्यात में भारत के हिस्से में भी थोड़ी सी गिरावट आई (तालिका 9)।

अंतरराष्ट्रीय ज़िंस कीमतें

2012 में ज़िंसों की कीमतों में गतिविधि कुछ अनिश्चित रही है जिससे प्रमुख वैश्विक घटनाएं परिलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए 2012 के पूर्वार्ध में मूल्य गतिशीलता में पण्य कीमतों में नरमी दिखी; खासकर ऊर्जा और धातुओं में, क्योंकि यूरोपियन प्रभुसत्ता कर्ज संबंधी मुश्किलें तेज हुईं और उभरती अर्थव्यवस्थाएं, खास कर चीन ने वृद्धि

तालिका 9 : विश्व निर्यातों में निर्यात वृद्धि और हिस्सा : देशों के बीच तुलना

(प्रतिशत)

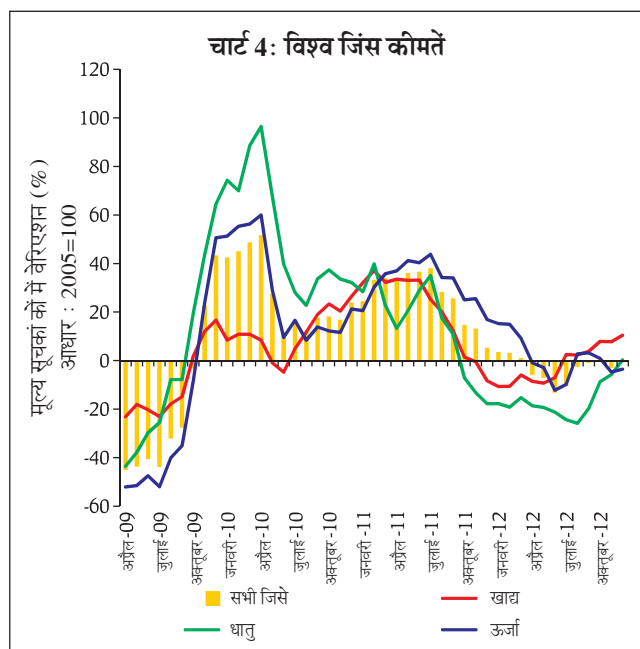
क्षेत्र/देश	2010-11	2011-12	ति2:2011-12	ति2:2012-13	2010-11	2011-12	ति2:2011-12	ति2:2012-13
	वृद्धि दरें				हिस्सा			
	1	2	3	4	5	6	7	8
विश्व	21.0	14.2	21.8	-4.2	100.0	100.0	100.0	100.0
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	17.3	11.5	17.9	-5.8	60.7	59.2	58.5	57.5
यूनाइटेड स्टेट्स	20.4	13.3	17.5	1.1	8.4	8.3	8.1	8.5
फ्रांस	8.2	9.5	14.2	-7.6	3.4	3.2	3.0	2.9
जर्मनी	12.9	12.4	20.0	-8.1	8.3	8.1	8.1	7.8
जापान	24.1	4.3	10.9	-9.1	5.0	4.5	4.7	4.5
ईडीईज	27.4	18.1	27.8	-1.0	39.7	41.1	42.3	43.7
सिंगापुर	27.3	11.9	15.9	-5.8	2.3	2.3	2.3	2.3
चीन, पीआर, मेनलैण्ड	30.6	16.1	20.6	4.5	10.4	10.6	11.2	12.2
भारत	40.5	21.3	44.7	-10.1	1.6	1.7	1.7	1.6
इंडोनेशिया	29.1	20.6	31.7	-12.9	1.1	1.1	1.1	1.0
कोरिया, रिपब्लिक ऑफ	27.2	12.7	21.4	-5.7	3.1	3.1	3.0	3.0
मलेशिया	20.1	11.4	16.7	-4.7	1.3	1.3	1.3	1.3
थाइलैण्ड	26.0	6.9	26.9	-6.4	1.3	1.2	1.4	1.3

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आइएमएफ

में गिरावट दिखाई (चार्ट 4)। तथापि वर्ष के दूसरे हिस्से में मूल्य दबाव स्पष्टतः ऊर्ध्वात्मक थे। जुलाई 2012 में ईरान के तेल आयातों पर ईयू द्वारा एम्बारगो लगाने के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में ऊपर की ओर दबाव आया जिसमें मध्यपूर्व के कई तेल उत्पादक देशों में बन रही राजनैतिक अस्थिरता ने भी योगदान दिया। इसके अतिरिक्त ईयू तथा यूएस के केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति नरमी को पुनर्नवीकृत करने तथा अमरीकी डॉलर की कमजोरी से अन्य औद्योगिक जिंसों में रिबाउंड आया। खाद्य कीमतों में ऊपरी दबाव मुख्य रूप से अमरीका, पूर्वी यूरोप, तथा मध्य एशिया में गर्म मौसम और सूखे की स्थितियों के कारण ही आया जिसने कि इन क्षेत्रों में मक्के और गेहूँ के उत्पादन को घटा दिया।

III. संभावनाएं

भारत के निर्यात में सुधार, अधिकांशतः, उन्नत तथा उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, दोनों की टिकाऊ रिकवरी पर निर्भर करेगा। हालांकि वैश्विक वृद्धि संबंधी चिंताएं हाल के महीनों में कुछ घटी हैं मगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की तत्काल रिकवरी की अपेक्षा अभी नहीं की जा सकती है। वैश्विक औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापार के व्यापक संकेतक सुझा रहे हैं कि अभी वैश्विक वृद्धि आगे सुदृढ़ नहीं हुई है। वैश्विक तत्त्वों के कारण निर्यात क्षेत्र के ढीले कार्यनिष्पादन को देखते हुए सरकार ने 26 दिसंबर 2012 को निर्यात प्रोत्साहन उपायों के दूसरे दौर की घोषणा



की। इनमें ये उपाय शामिल थे (i) मार्च 2014 के अंत तक चयनित रोजगार उन्मुख क्षेत्रों (जिनमें सभी सेक्टरों के छोटे और लघु लघुगो शामिल हैं) के लिए ब्याज सहायता योजना का विस्तार (ii) सार्क क्षेत्र के देशों के लिए एक्जिम बैंक के माध्यम से परियोजना निर्यातों हेतु 2 प्रतिशत ब्याज सहायता की 'पायलट योजना' की शुरुआत (iii) फोकस मार्केट योजना तथा विशेष फोकस मार्केट योजना, बाजार लिंकड फोकस उत्पाद योजना के स्कोप को बढ़ाना (iv) आधार अवधि पर जनवरी-मार्च 2013 की अवधि के दौरान अमरीका, यूरोपियन यूनियन तथा एशिया के देशों को किए गए वृद्धिशील निर्यातों पर प्रोत्साहन जनवरी 2013 में रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के प्रसार के लिए अदला-बदली (स्वैप) सुविधा की अनुमति दी। स्वैप सुविधा के अंतर्गत कोई बैंक, रिजर्व बैंक से, अपनी पात्र स्वैप सीमा तक, अमरीकी डॉलर खरीद सकता है और साथ ही इतनी ही अवधि के स्वैप्स हेतु प्रचलित बाजार दरों पर स्वैप की शर्तों के अनुसार इतनी ही राशि के अमरीकी डॉलर बेच सकता है। स्वैप अवधि के अंत में बैंक, रिजर्व बैंक के साथ रूपए के समक्ष अमरीकी डॉलरों का विनिमय कर सकेगा। रिजर्व बैंक ने वस्तुओं अथवा निर्यात किए गए सॉफ्टवेयर की पूर्ण निर्यात वैल्यू की प्रतिनिधिक राशियों की प्राप्ति तथा प्रत्यावर्तन की अवधि में भी बढ़ोतरी की, जो पहले निर्यात की तारीख से छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने की गई और बाद में इसे 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया है।

इन उपायों के बावजूद प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को किए जाने वाले निर्यातों में त्वरित बहाली अनिवार्यतः होनी कठिन ही है: जब तक कि उन्नत तथा ईएमडीई, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि जोर नहीं पकड़ती। कुछ प्रमुख आयात मर्चों में आयात को रोकने के लिए सरकार ने मांग पर रोक लगाने के कुछ उपायों की घोषणा की। उदाहरणतः जनवरी 2013 में सोने पर कस्टम ड्यूटी 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दी गई। इसी प्रकार सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को डीजल की खुदरा कीमतें धीरे-धीरे बढ़ाने की अनुमति दी है। भारत के समग्र व्यापार घाटे पर इनका प्रभाव दिखना अभी बाकी है और मध्यावधि में दिखने की अपेक्षा है, बशर्ते कि वैश्विक परिदृश्य में भी काफी सुधार हो।